विभिन्न कालखंडों के बीचः भारत की विकट स्थिति और शानदार रणनीति
Between the Times: India's Predicaments and its Grand Strategy

ऐशले जे. टैलिस
Ashley J. Tellis
December 3, 2012

भारत की स्वाधीनता की पूर्वसंध्या पर कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को दिशा देने में कितना कामयाब होगा. उस समय कितने ही लोग ऐसे थे जो भारत के अस्तित्व को संदेह की दृष्टि से देखते थे और मानते थे कि भारत मुश्किल से कुछ साल या बहुत हद तक कुछ दशकों तक ही टिक पाएगा. लोगों के बीच बहस केवल इस बात पर होती थी कि वह समय कब आएगा जब भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे और चर्चिल की यह बात सबके दिमाग में घूमा करती थी, "भारत इक्वेटर की तरह ही मात्र एक भौगोलिक शब्द है. यह कोई संयुक्त देश नहीं है." तब से कुछ लोग यही चर्चा करते रहते थे कि अगर भारत एकजुट बना रहा तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.

लेकिन आज भारत की एकता पर कोई सवाल नहीं उठाता. भारतीय इतिहास के सबसे बड़े करिश्मे के रूप में भारत भारी गरीबी और विविधता के बावजूद एकजुट बना रहा है और अपनी क्षेत्रीय अक्षुण्णता को बरकरार रखने में कामयाब रहा है. हाँ, यह सही है कि भारत ने एक युद्ध में पराजय का मुँह देखा है, लेकिन अत्यंत विवादग्रस्त और अनिश्चित क्षेत्रीय परिवेश में स्थित होने के बावजूद इसकी क्षेत्रीय अक्षुण्णता बरकरार है. और सबके लिए हैरानी की बात तो यह है कि भौतिक साधनों की भारी कमी के बावजूद भारत अपनी राजनैतिक स्वायत्तता को बचाने में कामयाब रहा है.

जिन लोगों को भी भारतीय सहयोगियों के साथ वार्ता की मेज़ के दूसरी ओर बैठने का सौभाग्य मिला है वे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भारत अपने हितों के संरक्षण में सक्षम नहीं है. जब मैं सिविल परमाणु संधि वार्ता पर काम कर रहा था तो हमारे दल पर अक्सर यह दोष मढ़ा जाता था कि हम अमरीकी हितों के संरक्षण में असमर्थ हैं और हाँ, कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो ऐसे दोष अपनी टीम पर भी मढ़ देते थे. लेकिन किसी भी अमरीकी सदस्य ने वार्ता से यह मानकर बहिष्कार नहीं किया कि भारत अपने बल पर टिके रहने में असमर्थ है !

आज साठ साल पूरे हो गये हैं. विश्व शक्तियों में भारत की मज़बूत दावेदारी उदीयमान शक्ति के रूप में होने लगी है. अमरीकियों के दिमाग में दक्षिण एशिया के संदर्भ में इसी अकेले वाक्यांश की गूँज बार-बार सुनायी देती है. इसका उल्लेख अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में होने लगा है और इसने अमरीकी विदेश नीति के सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया है. लेकिन इस बारे में भारत का अपना अलग दृष्टिकोण है. अमरीका और भारत के भावी संबंधों को समझने के लिए इस परिप्रेक्ष्य को समझना ज़रूरी है.

भारत सबसे पहले अपने-आपको एक ऐसे विकासशील देश के रूप में ही देखता है जिसे अभी बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना है. जब भी भारतीय अपने बारे में और दुनिया में अपनी भूमिका के बारे में सोचते हैं तो वे यह नहीं सोचते कि वे विश्व को कैसा आकार देना चाहेंगे, बल्कि वे उसका सामना कैसे कर पाएँगे. इसलिए इस बात पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि स्वाधीनता से अब तक भारत की शानदार रणनीति आत्मनिरीक्षण की रही है. हालाँकि स्वाधीनता के बाद के कुछ वर्षों तक यह रणनीति केवल शब्दाडंबर तक ही सीमित थी. यही कारण है कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है.

क्या कारण है कि अनेक बाहरी लोग भारत के बारे में शिकायत करते हुए अनिवार्यतः यह धारणा बना लेते थे कि भारत का रुख हमेशा प्रतिक्रिया का ही रहा है. इसका वास्तविक कारण यही रहा है और शायद सही भी रहा है कि दुनिया में सफलता सिद्धांततः तभी मिलती है जब अपने देश में आप राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रबंधन के क्षेत्र में सफल होते हैं. अब विभिन्न स्तरों पर होने वाले कायाकल्प के तीन ऐसे स्थायी कारण हैं जिनके कारण नयी दिल्ली ने दुनिया के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है.

पहला स्थायी कारण यह है कि आर्थिक विकास के प्रति उसका स्थायी जुनून. इस बारे में भारत का सचमुच कायाकल्प हुआ है. जहाँ भारत ने आरंभ में आर्थिक विकास के प्रबंधन के लिए मुख्यतः स्वदेशीकरण और सरकारी नियंत्रण को अपनाया था, वहीं अब इसका दृष्टिकोण बदलने लगा है और अब वैश्वीकरण और बाज़ार की शक्तियों के लिए ज़्यादा गुंजाइश होने लगी है. यह संक्रमण अभी भी अधूरा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसीके कारण ही न केवल रणनीति के स्तर पर बल्कि राजनयिक स्तर पर भी अमरीका और भारत के संबंध मज़बूत हो पाए हैं. लेकिन जिस बात का सबसे अधिक असर होता है वह है चैकबुक और उनकी जेबें. इन संबंधों का भविष्य इसी कारण उज्ज्वल है क्योंकि भारत की शानदार रणनीति में आर्थिक पक्ष का कायाकल्प बहुत महत्वपूर्ण है.

दूसरा स्थायी कारण यह है कि भारत ने आरंभ से ही राज्य की क्षमता विकसित करने और नागरिकों के सशक्तीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. यद्यपि यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन इस क्षेत्र में भारत की सफलता पूरी तरह से उसके द्वारा घरेलू स्तर पर उठाये गये कदमों पर ही निर्भर करती है. अमरीका जैसे सदाशयी बाहरी लोग इस बारे में भारत की कुछ मदद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ही यह संभव है. भारत अपनी संस्थाओं को किस प्रकार के विकल्प देता है और अपने लोगों में कितना निवेश करता है, इसी बात पर भारत की रणनीति की सफलता निर्भर करती है. अपने लक्ष्य हासिल करने में राज्य और बाज़ार के बीच भारत किस प्रकार संतुलन बैठाता है इस पर अब बड़े पैमाने पर वाद-विवाद चल रहा है. अमरीका पीछे से भारत की कुछ मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका भारत को ही निभानी होगी.

भारत की शानदार रणनीति का अंतिम पहलू सुरक्षा की प्रतियोगिता को न्यूनतम रखते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने की इच्छा है. भारत अब तक रूढ़िवादी रणनीति ही अपनाता रहा है, क्योंकि वह अपनी कमज़ोरी को अच्छी तरह जानता था. अपनी भीतरी कमज़ोरी और अनिश्चित परिवेश के कारण ही भारतीय नीति-निर्माता रक्षात्मक नीति अपनाते रहे हैं. उनका ध्यान विश्व में भारत की स्थिति को

मज़बूत करना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को और बिगड़ने से रोकना था. इसलिए भारतीय नीति के मूल में हमेशा विकल्पों को बंद न करने का भाव ही रहा है.

यह दृष्टिकोण पहले से ही चिंतित अमरीका को और भी परेशान कर देता है, क्योंकि अमरीका भारत को एक ऐसे उत्साही देश के रूप में देखना चाहता है जो अपने परिवेश को बदलने के लिए उत्सुक हो, न कि एक ऐसे देश के रूप में जो अपनी इक्विटी को बचाने में ही लगा हो. परंतु अमरीकी सरकार को भी यह याद रखना चाहिए कि भारत की रक्षात्मक स्थिति का गहरा संबंध उसके अपने विकास के चरण से है. जिस दिन भारत अपनी उन तमाम चुनौतियों का सामना करने में सफल हो जाएगा जिनके कारण नीति-निर्माता अपना संतुलन बनाये रखने में लगे रहते हैं, भारत मात्र समायोजन करने के बजाय विश्व को आकार देने का प्रयास करेगा.

भारत आज अपने को अलग-अलग कालखंडों के बीच पाता है. इसने यह मूल कार्य तो निपटा लिया है कि व्यापक अर्थों में राजनैतिक निष्ठा के संरक्षण के लिए देशों की क्या भूमिका होनी चाहिए. यह कामयाबी भी बहुत मुश्किल से हासिल हुई है, लेकिन यह काम भारत के लिए उस समय और भी जटिल हो जाता है जब उसके विस्तारित पड़ोस में नयी महाशक्तियाँ और नयी चुनौतियाँ सामने आने लगती हैं तो लोकप्रिय आकांक्षाएँ भी सिर उठाने लगती हैं.

जैसे ही भारत कामयाब होता है भारत और अमरीका की और उनके लोगों की उम्मीदें भी उससे बढ़ जाती हैं. इसलिए भारत अपने-आपको और अपनी भूमिका को किस तरह समझता है और उसमें अपना योगदान करता है, इसका सरोकार आगे आने वाले वर्षों में अमरीका- भारत की भागीदारी से जुड़े सभी लोगों से है.

अमरीका को भी यह समझना होगा कि भले ही भारत कोई भी लेबल इस्तेमाल करे, लेकिन अपने आकार, अपने इतिहास और अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही वह अपनी भूमिका निभाएगा. भले ही कैसी भी परिस्थितियाँ हों भारत कभी-भी अमरीका के साथ ऐसे किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जैसा कि अमरीका चाहता है. सच तो यह है कि भारत अपना प्रारूप खुद ही तैयार करेगा और आवश्यक नहीं है कि इससे अमरीकी हितों को चोट ही पहुँचे. वास्तव में वाशिंगटन को अपने-आप से यह नहीं पूछना चाहिए कि भारत अमरीका के लिए क्या कर सकता है बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए कि भारत को क्या होना है, भारत को आज़ाद रहने के साथ-साथ मज़बूत होना है या कमज़ोर?

बुनियादी तौर पर मज़बूत भारत ही अमरीका के हित में है. जब मैं डब्ल्यू, बुश के प्रशासन में काम करता था तब भी इस परिप्रेक्ष्य को समझा जा चुका था. हम भारत के साथ इस उम्मीद से सहयोग नहीं कर रहे थे कि इसके बदले भारत को भी कुछ करना होगा. हमने सिर्फ़ इस उम्मीद में अमरीका-भारत संबंधों में कायाकल्प लाने के लिए ज़ोर नहीं दिया था कि भारत हमारे सीमित हितों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देगा. बल्कि हमें विश्वास था कि भारत अपने ही बल पर स्रोतों की खोज करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश और उदीयमान शक्ति के रूप में यह एशिया में शक्ति संतुलन करने में सफल हो जाएगा. अंततः यह एक साथ भारत और अमरीका दोनों

ही देशों के हित में होगा. यदि भारत की विदेश नीति में इस तथ्य के मद्देनज़र इस अवसर को और इसकी क्षमता को स्वीकार कर लिया जाता है तो अमरीका-भारत संबंधों के भविष्य की अमरीकी चिंता बहुत हद तक मिट सकती है. और पिछले बीस वर्षों में मुझे लगता है कि हमने इस दिशा में अच्छी शुरुआत कर दी है.

ऐशले टैलिस कारनेई ऐंडोमैंट इंटरनैशनल पीस में सीनियर ऐसोशिएट हैं. वे 'कैसी' के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार मंडल के सदस्य हैं. इस लेख का पाठ 27 *सितंबर* , 2012 *को "भारतः कायाकल्प के दो दशक" विषय पर 'कैसी' की* 20*वीं वार्षिक संगोष्ठी में दिये गये उनके भाषण से लिया गया है.*

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@hotmail.com>